



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51

संख्या: 70

प्रभात

कोटा, मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

क्या बंगाल में भाजपा का “ट्रंप कार्ड” साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने “भद्रलोक” (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक “ट्रम्प कार्ड” के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरबी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता

बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन ‘भद्रलोक’ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत हिंदू राष्ट्र है’

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर इस बात पर जोर देते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाता रहेगा।

भागवत ने कोलकाता में आरएसएस के ‘100 व्याख्यान माला’

- संघ प्रमुख भागवत ने यह दावा करते हुए कहा, संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो भी ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है यह सत्य है।

कार्यक्रम में कहा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। हमें नहीं पता यह कब से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हमें संविधान को मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीएमसी चुनाव में एक हुई मुम्बई की “फर्स्ट फैमिली”

20 सालों में यह पहली बार है जब उद्धव और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। मुंबई की राजनीति में ‘पहला परिवार’ माने जाने वाले ठाकरे परिवार ने सोमवार सुबह एक बड़े चुनावी पुनर्मिलन की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने होने वाले बृह-मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर इस परिवार में आधिकारिक सहमति बन गई है।

पिछले 20 वर्षों में यह पहला अवसर होगा, जब ठाकरे परिवार के दो सबसे बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

इस बीच, कांग्रेस इस व्यवस्था का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थिति महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर तनाव को दर्शाती है, खासकर ठाकरे भाइयों के एकजुट होने के बाद। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में एमवीए को झटका लगने के बाद भी, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वापसी की उम्मीद है।

बड़े संकटों के दौर में, दलितों, मुसलमानों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर, देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा जताया है।

- बीएमसी की 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 157 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
- इस नई व्यवस्था में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सहयोगी दलों, कांग्रेस व एनसीपी (शरद पवार) को कोई जगह नहीं मिली है इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित नहीं रहे और भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस ने भी इन चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक हल्की सी चुनौती पेश की।

इस सफलता का श्रेय कांग्रेस नेता विजय वडेड़ीवार, कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रतिभा धनोरकर और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाले को जाता है।

कांग्रेस द्वारा जीते गये कुल 34 नगर परिषद अध्यक्ष पदों में से आठ सीटें चंद्रपुर जिले की और तीन सीटें बुलढाणा जिले की थीं।

विश्वजोत कदम अपने गढ़ को बचाने में सफल रहे, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधायक

अमित देशमुख अपनी पकड़ बनाए रखने में असफल रहे।

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने कुल 288 में से 120 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 36 पद मिले।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सूत्रों ने बताया कि शिव सेना बीएमसी की 227 सीटों में से 157 पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शेष 70 सीटों पर उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवार उतारेंगी।

इस व्यवस्था के बाद, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना-नेतृत्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितों के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केन्द्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितों के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आयवित्त वर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथेनॉल युक्त पेट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
- लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।

की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी ऐथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।

वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी

गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ई20 पयूल कोरोसिव (संश्लारक) प्रकृति का है और अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों के इंजनों की उम्र कम कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में माइलेज में 3 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट और पयूल सिस्टम तथा रबर गैस्केट को नुकसान की आशंका जताई गई है।

नितिन गडकरी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें ‘पेड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आईपीएस पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशनों पर प्रोविज़नल तौर पर विचार करें’

जयपुर, 22 दिसंबर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार

- केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

करे। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्त तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कीटनीती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के पयूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है वहीं स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी

द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई थी।

इंडियन शुगर एण्ड बायो एनर्जी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की वार्षिक आम बैठक के दौरान, दीपक बलानी, महासचिव, आईएसएमए ने कहा: “भारत ने ई 20 के लक्ष्य को बहुत तेजी से हासिल किया है। लक्ष्य 2030 तक 20 प्रतिशत ब्लैंडिंग का था, लेकिन हम इसे पांच साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जो काम ब्राजील जैसे देशों ने 20 साल में किया, हमने वह सिर्फ 7-8 साल में कर दिखाया।

ऐथनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथेनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राजील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीबाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील को

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “बैड डील” करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट – एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “खराब समझौता” करार देते हुए कहा कि यह “बहुत अधिक देने” तथा “बहुत कम” प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूजीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंग्टन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में “सबस्टेंस” का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो “न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी” के नेता और सरकार में गठबंधन साझेदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी “खेद सहित” इस समझौते के खिलाफ

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूजीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, “हम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।” उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों

की रक्षा करने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक खराब समझौता है। यह देता बहुत ज्यादा है, खासकर आप्रवासन के मामले में, और न्यूजीलैंडवासियों के लिए बहुत कम प्राप्ति करता है, जिसमें डेरी उत्पाद क्षेत्र भी शामिल है।

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एसएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 1०० दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया । स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 1५ दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी ।

। लोग पीड़ी दर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी। यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2००5 बनाया। 2०09 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्त्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6००0 करोड रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी । केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 1५ दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 4० प्रतिशत से अधिक न हो एवं 6० प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 1० प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 4० प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 1० प्रतिशत से भी कम भुगतान पडता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं । कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया । उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंगे सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंगे गाड़ी खरीद ली थी । भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था । सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2००9 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 1५ दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित करवाया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजान में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरी में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल

जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 1५.५ करोड जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 1२ करोड लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 2०० करोड मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 1०० दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 4५ दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 1०० दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 1२५ दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2०1५ में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 1० वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं । वह इस योजना के अंतर्गत 4० प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे ? अब तक राज्यों पर 1० प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पडता था जो बढ़कर अचानक 4० प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 4० प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए ।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि शर्ष्यों को तोड मरोड करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख,राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू,राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है । यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों को केंद्रीकरण कर दिया है । इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है । इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 7०० किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग ६५० किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1९९० के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2००९ में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2०2४ में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 2० नवंबर 2०25 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 1०० मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 1०० मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2००5 को 1०० मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 1०० मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे ५०० मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस ५०० मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 1०० मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का ९८ प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि ९० प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

८1४वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह

पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री को स्वागत कर दस्तारबंदी कर उस की मुबारक दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री

2०47 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु,

जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं।

इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एग्म में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिवर दिल्ली भेजा गया है।

एग्म के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिडा के रहने वाले भोमाराम (५) पुत्र भैराम को बार-बार दौरे पड़ने की समस्या पर 1५ दिसंबर को एप्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्पेटिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग में मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

नवीन कार्यों के संबंध में सरकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

नवीन कार्यों के संबंध में सरकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

पारदर्शी ढांचा लागू हो रहा है, तब उसी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा करना जनभावनाओं को भ्रमित करने का प्रयास है।

सरकार की नीति केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। जून 2०2५ में शुरू की गई अरावली ‘ठीन वॉल’ परियोजना इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। चार राज्यों के 2९ जिलों में पांच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाकर 2०3० तक करोड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल बताती है कि सरकार अरावली को केवल बचाने नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करना चाहती है।

अरावली प्रकरण में वास्तविक संघर्ष पर्यावरण और विकास के बीच नहीं, बल्कि तथ्य और भ्रम के बीच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और केंद्र सरकार की नीति यह स्पष्ट करती है कि अरावली के संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वर्षों से चली आ रही अस्पष्टताओं को समाप्त कर एक वैज्ञानिक, न्यायिक और जवाबदेह ढांचा स्थापित किया गया है।

आज आवश्यकता है कि अरावली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति तथ्यों के साथ खड़ी हो, क्योंकि अरावली का प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

केंद्रीय मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे अजमेर, बुलंद दरवाजे पर पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया

एसपी वंदिता राणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताग पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमद ने लंघर शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताग पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमद ने लंघर शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताग पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमद ने लंघर शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।

जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं। इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एग्म में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिवर दिल्ली भेजा गया है।

एग्म के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिडा के रहने वाले भोमाराम (५) पुत्र भैराम को बार-बार दौरे पड़ने की समस्या पर 1५ दिसंबर को एप्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्पेटिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग में मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

नवीन कार्यों के संबंध में सरकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



सार-समाचार

‘सुशासन पखवाड़े में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें’

कोटा, (निसं)। साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी शिविरों में अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करें। साथ ही सुशासन पखवाड़े के अन्तर्गत सभी प्रकार के ऑनलाईन माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी शिविरों में विभागीय अधिकारी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की उचित प्रकार से सुनवाई करते हुए उन्हें त्वरित राहत दें। सुशासन पखवाड़ा एवं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किए जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कार्यक्रमों की सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर अपलोड भी करें। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई, निर्देश दिए कि समयबद्धता के साथ इनकी क्रियान्वित की जाए। विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। संपर्क पोर्टल की समीक्षा कर निर्देश दिए कि 30 दिवस से अधिक समयावधि वाले प्रकरणों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाए अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में बाईक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से बाईक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झालावाड़ हाल कोटा निवासी रामलखन बाईक से जाते समय रास्ते में बाईक फिसलने से बाईक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में घायल युवक को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अनंतपुरा थाने के एएसआई घमंडी लाल ने बताया कि झालावाड़ के पनवाड़ हाल कोटा में किराये से रहने वाला रामलखन मेघवाल (24) बाईक से गोबरिया बावड़ी से ग्लोबल चौराहे की तरफ जाते समय बाईक फिसलने से बाईक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाईक सवार रामलखन घायल हो गया। जिसे उपचार के लिये मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

कृष्णा-भोग कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कोटा, (निसं)। श्रीराम सेवा समिति के तत्वावधान में सेवा, संस्कार एवं आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरड़ा बस्ती में कृष्णाभोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तथा उपस्थित बच्चों के साथ-साथ बस्ती के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रीराम सेवा समिति की सदस्य सरोज, प्रीति सहित अन्य महिला सदस्यों ने बद्-चढ़कर भाग लिया।

खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। प्रगति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रीको रामपुर में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रथम दिन प्रतियोगिता का शुभारम्भ महाविद्यालय की सहायक प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉ.सविता चौधरी ने फीता काटकर किया।

‘निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर, नहीं जमा कराया तो लग सकती है 100 प्रतिशत पैनल्टी व ब्याज’

कोटा, (निसं)। राज्य में सभी जिलों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (श्रमिक) कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 लागू है जिसके तहत सरकारी/वाणिज्यिक/निजी (आवासीय) भवनों व निर्माण कार्यों की लागत पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (सेस) देय है। उपकर नहीं देने वाले भवन मालिकों/नियोजकों को संयुक्त श्रम आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।

संयुक्त श्रम आयुक्त शमिता जैन ने बताया कि प्रारंभ में भवन मालिक/नियोजक को निर्माण से संबंधित दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस के बाद उपकर (सेस) जमा नहीं कराने पर श्रम विभाग स्वयं निर्माण की लागत निकालकर भवन मालिक के विरुद्ध एकतरफा उपकर (सेस) निर्धारण आदेश जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी

■ संयुक्त श्रम आयुक्त ने नोटिस जारी किए

कर उपकर निर्धारण संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।

नियत समय पर राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में जिला कलक्टर (वसूली) को प्रकरण प्रेषित किये जायेंगे। उपकर राशि देय होने की अवधि में जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में 24 प्रतिशत वार्षिक दर से नियोजक पर ब्याज आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त उपकर निर्धारण के आदेश की दिनांक से निर्धारित अवधि में उपकर राशि के भुगतान/जमा नहीं कराने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है।

निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना 30 दिवस में दें:- उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी तक किसी भी वर्ग या निर्माण कार्य पर उपकर राशि की छूट नहीं है। भवन निर्माण करने वाले

मालिकों/नियोजकों को निर्माण कार्य के प्रारंभ करने की सूचना 30 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग को दिया जाना आवश्यक है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने या उपकर राशि निर्धारण होने की 30 दिवस की अवधि में, जो भी पहले हो, उपकर संग्रहक को जमा कराया जाना आवश्यक है। यदि किसी प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 30 दिवस में देय उपकर राशि जमा करायी जाना आवश्यक है। नियोजक द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर देय उपकर अग्रिम भी जमा कराया जा सकता है।

श्रम कल्याण की योजनाओं में व्यय होती है उपकर की राशि:- संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि उपकर (सेस) के तहत वसूली जाने वाली राशि निर्माण श्रमिकों के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं

में व्यय की जाती है। जुलाई 2009 के बाद निर्मित सरकारी/वाणिज्यिक/निजी आवासीय भवनों व निर्माण कार्यों को उपकर (सेस) के दायरे में रखा गया है। जिनमें से 10 लाख रुपये से कम लागत के बनाए गए केवल आवासीय भवनों को उपकर सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।

अगर 10 लाख रुपये की लागत से ज्यादा की लागत से अगर कोई आवासीय भवन बनता है तो उससे भी एक प्रतिशत उपकर (सेस) वसूला जाएगा। व्यावसायिक भवन निर्माण करवाने पर कोई छूट नहीं है। कोई भी निर्माणकर्ता द्वारा कोटा विकास प्रधिकारण नगरपालिका/नगर निगम में नक्शा स्वीकृति के समय उपकर की अनुमानित राशि जमा करवाई गई है तो भी अंतिम उपकर निर्धारण राशि कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, कमरा नंबर 32, कलेक्ट्रेट परिसर कोटा में जमा करवाया जाना आवश्यक है।

फायरिंग के तीन आरोपी पकड़े

कोटा (निसं)। रामपुरा कोतवाली इलाके में फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 26 नवम्बर को फरियादी ने रामपुरा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि घर के पास गली में खड़ा था, तभी रोहित सिंगोर, अंकुश व अन्य बाईक पर आये और जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। रिपोर्ट में कहा कि फायर मिस होने से वह बाल-बाल बच गया। शहर एसपी ने कहा कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले का खुलासा करने के लिये पुलिस उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी महेन्द्र मारू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई (निसं)। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए हैं, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का जश्न मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है।

आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना

■ 25 हजार या अधिक की डायमंड ज्वैलरी की खरीद पर ग्राहकों को 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉयन मुफ्त मिलेगा

चाहते हैं।

इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25

ग्राम का गोल्ड कॉयन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा।

सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वैलरी की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 20 फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वैलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टाइल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

सार-समाचार

हाइती गौरव सम्मान 2026 का आमंत्रण पत्र सौंपा

रामगंजमण्डो, (निसं)। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में आगामी 5 जनवरी को आयोजित होने वाले अष्टम हाइती गौरव सम्मान 2026 कार्यक्रम के लिए सोमवार को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र सौंपे गए। हाइती गौरव सम्मान 2026 आयोजन समिति के संरक्षक एवं लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यक्रम संयोजक के. के. शर्मा कमल, स्पर्धा सिविल सर्विसेज अकैडमी के निदेशक संजय शर्मा, होलसेल व्यापार संगठन हाइती संभाग के अध्यक्ष पंकज बागड़ी के सानिध्य में समिति पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कोटा पीयूष समरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह यादव को आमंत्रण पत्र सौंपकर कार्यक्रम में पधारने एवं हाइती की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आग्रह किया।

होटल में तोड़फोड़ व चोरी के आरोपी गिरफ्तार

कोटा (निसं)। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 19 दिसम्बर को विज्ञान नगर इलाके में स्थित अलकरीम होटल के मैनेजर ने थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि होटल पर पांच व्यक्ति आये और खाना खाने के बाद बिल को लेकर उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ करने लगे एवं गल्ले में रखे रूपये निकालकर चुराकर ले गये। विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए जिला बुंदी के थाना डाबी, बडफू निवासी मुकेश (25), धारा (29), राकेश गुड्डू (23), जगदीश (29) एवं राजमल (30) को बुन्दी से डिटेन कर अनुसंधान के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। टीम जीवन दाता का सेवा से ही सरोकार देखने को मिल रहा है, जहां पर निरंतर मरीजों की सेवा कर उन्हें जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है। लार्यंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सतीश शर्मा ने मरीज बाबूलाल को लगातार पांचवीं बार बी नेगेटिव एसडीपी डोनेट की है।

कार्यालय नगर परिषद बारां		
क्रमांक-नपवा/तामीर शाखा/2025/8626	दिनांक-18.12.2025	
सार्वजनिक विज्ञप्ति		
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्राण श्री प्रेमचन्द बंसल निवासी बारां का आवेदन पुर्नगठन चाहने वास्ते प्राप्त हुआ है जिसमें पट्टा विलेख संख्या 1228 दिनांक 19.05.2008 भूखण्ड संख्या मिल माप कुल 1375 वर्गफुट में से 1175 वर्गफुट आवासीय व 200 वर्गफुट व्यवसायिक, योजना कोटा रोड बारां का श्रीमति प्रवीणा कुमारी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी बारां के नाम जारी किया। तत्पश्चात पट्टाधरक द्वारा जर्वे रजिस्टर्ड बननामा पत्र दिनांक 19.10.2020 से उक्त भूखण्ड में से 10125 वर्गफीट, व जर्वे रजिस्टर्ड बननामा पत्र दिनांक 28.09.2020 से 1800 वर्गफीट, को श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्राण श्री प्रेमचन्द बंसल को बेवान कर दिया गया, एवं पट्टा विलेख संख्या 8306 दिनांक 07.02.2024 एकल भूखण्ड कुल माप 7233.6 वर्गफीट में से 4110 वर्गफीट व्यवसायिक व 3123.6 वर्गफीट आवासीय का श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्राण श्री प्रेमचन्द बंसल के नाम किया जाना है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति नय दस्तावेजों के साथ कार्यालय हजाम में प्रस्तुत करें। बाद अवाधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति नान्य होनी होगी।		



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
₹2,000 + करोड़ की स्वीकृति

राज्य परियोजनाओं से कृषकों
को ₹1,200 करोड़ का हस्तांतरण

मुख्य अतिथि

श्री शिवराज सिंह चौहान

माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अध्यक्षता

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

नागौर जिले में ₹351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

राशि हस्तांतरण

कृषि एवं उद्यानिकी योजनाएं

31,600 कृषकों को ₹200 करोड़

कृषि आदान-अनुदान

5 लाख कृषकों को ₹700 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

18,500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना

4.50 लाख पशुपालकों को ₹200 करोड़

23 दिसम्बर, 2025 | अपराह्न 12:00 बजे | डांगावास, मेड़ता सिटी (नागौर)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

बजरी माफिया से सांठगांठ पर 1 1 पुलिस निरीक्षकों पर गाज गिरी

पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने प्रदेशभर में किया डिकॉय ऑपरेशन

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और गंभीर लापरवाही रखने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा डिकॉय ऑपरेशन करने के बाद यह कार्रवाई हुई।

प्रदेशभर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में पांच पुलिस निरीक्षकों को तत्काल निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य को लाइन हाजिर किया

■ **पांच पुलिस निरीक्षक निलंबित, अन्य 6 को लाइन हाजिर किया**

गया है।

एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने

आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था,बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी।

जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरीनी, अजमेर के पीसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाडी व नान्ता, दोसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगारार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थाना अधिकारियों को

लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं : पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं।

इससे पहले नवंबर माह में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो एफआईआर दर्ज न करने, परिवारियों से दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम की शिकायतों पर हिलाई, एसपी ऑफिस में प्राप्त परिवारों में परिवार अनुभाग की कार्यप्रणाली, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली एवं कार्यशैली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन किया गया था।



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की।

के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठियां, स्कूलों एवं कॉलेजों में विचार संगोष्ठियां तथा भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी। इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहित्यजादों की शहाबाद व किशनगंज ब्लाक की सहरीया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 11 करोड़ की लागत से 22 किमी. सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 5 साल पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। स्वतंत्रता के दशकों बाद तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। जिसके तहत सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आक्विफरी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर

- **प्रदेश में 75 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें तथा 68 गुल बनाकर 15983 बसावटों को जोड़ा गया**
- **केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेड़ता में 2089 करोड़ रुपये लागत की 1216 पीएमजीएसवाई सड़कों की सौगात देंगे**

आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि, कृषक सौगात देंगे। जिनकी अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ होगी।

गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश

में लगभग 12086 करोड़ रूपये की लागत से 49730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 14043 किमी. सड़कों के चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चर्यानित “शू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क” को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ नयी सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों के नेटवर्क को और अधिक

मजबूत करना भी आवश्यक है। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण-सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। अब तक प्रदेश में 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किमी. की 903 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 पुलों

एम.एन.आई.टी. में प्रस्तावित ट्रेड फेयर पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीपीजे सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिवाक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अभिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और

- **बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित 3 दिवसीय इस ट्रेड फेयर में सोलर क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों निर्माता और सेवा कंपनियां भाग लेंगी**
- **याचिका में कहा गया कि, “संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।”**

शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए हैं, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का ख़र्च मनाना सकेगा। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है। आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा। सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 20



फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वेलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टायल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

“जयपुर ज्वैलरी शो” कला-विरासत और परंपरा का उत्सव : प्रेमचंद बैरवा जे.ई.सी.सी. में जे.जे.एस. संपन्न हुआ, बीते 4 दिनों में करीब 4 6 हजार विजिटर्स ने की शिरकत



जयपुर ज्वैलरी शो के समापन समारोह में सोमवार को उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वैलरी प्रस्तुति के अवार्ड देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

जयपुर (कासं)। जयपुर आभूषण की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है और जयपुर ज्वैलरी शो इस शहर की समृद्ध विरासत, परंपरा और कला का उत्सव है। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर ज्वैलरी शो 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों और ईए ऑफ दूइंग बिजनेस के जरिए इस उद्योग को सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जेजेएस वार्ड्स चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने कहा कि अपने शुरुआती

- **18 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा आगामी संस्करण**

वर्षों में मात्र 67 बूथों से शुरू होकर आज 1227 बूथों तक पहुंचना इस शो की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। आज यह एजीबिशन देश की सबसे बड़ा बी2बी और बी2सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है।

जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने बेस्ट बूथ अवॉर्ड्स की घोषणा की। उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वेलरी प्रस्तुति के लिए 18 वर्ग मीटर से ऊपर बेस्ट बूथ ज्वेलरी श्रेणी में विजेताओं में पहला स्थान बिरछीचंद घनश्याम दास ने जीता। दूसरे स्थान पर

सार-समाचार फैशन और ज्योतिष का अद्भुत संगम



जयपुर । अलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलाजी कॉन्क्लेव (एआईएसी) सीजन-2 के अंतर्गत आयोजित रिलेटिंग जोडियक फैशन शो ने फैशन और ज्योतिष के अद्भुत संगम को भव्य मंच पर प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अनूठे आयोजन में राशियों की ऊर्जा, रंगों और भावनाओं को फैशन के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. मेधा शर्मा ने बताया कि यह भव्य आयोजन ऑलमाइटी इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल वास्तु अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। शो की परिकल्पना और निर्देशन, मिससे इंडिया इंटरनेशनल दीपिका सैनी ने संभाली। इस विशेष फैशन शो में प्रीति सचदेवा, युविका जैन, मीनाक्षी सोलंकी, अमृता टांगियावा, ममता जायसवाल, अंशु वाघवा और इंद्रजीत दास ने विभिन्न राशियों पर आधारित डिजाइनों को आत्मविश्वास, गरिमा और सौंदर्य के साथ रैप पर प्रस्तुत किया। प्रत्येक प्रस्तुति में संबंधित राशि के रंग, व्यक्तित्व और कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिला। शो की विशेष आकर्षण रही शोर्ट्स पर आरजे देवांगना, जिन्होंने रैप पर अपनी दमदार उपस्थिति से समा बांध दिया। मंच पर मेघ की ऊर्जा, सिंह की शाही भव्यता, तुला का संतुलन और कर्क की कोमलता फैशन से सजीव हुई।

ब्राइट फ्यूचर स्कूल में क्रिसमस पर्व मनाया

जयपुर । जनता कॉलोनी स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ “क्रिसमस” पर्व मनाया। लाल और सफेद रंग की पोशाक पहनकर छोटे-छोटे बच्चों ने क्रिसमस कैरौल की धुन पर गाकर और नाचकर बुखारियां फैलाई। अनर्गल छोटे सांता क्लॉज ने माहौल को जादुई बना दिया और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार और मनमोहक पल बनाए। यह उत्सव हंसी, संगीत और एकजुटता की भावना से भरा था। उत्साह को बढ़ाते हुए, डायरेक्टर तेजेंद्र शर्मा और गौरव तेज शर्मा ने बच्चों को बेस्ट डॉसर, बेस्ट ड्रेस्ड, बेस्ट पोस्टर मेकर और अन्य कैटेगरी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

वीकेंड के बाद भी सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में रौनक बरकरार



जयपुर । सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 में वीकेंड के बाद भी उत्साह और चहल-पहल कम नहीं हुई। सोमवार को मेले के पाँचवें दिन सामान्य कार्यदिवस होने के बावजूद मेला परिसर में भीड़ देखने को मिली। शिल्प, हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने मेले को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया।

परिवारों के साथ आए दर्शकों ने विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल के स्कूली बच्चों ने भी मेले का भ्रमण किया।

<

